क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

दैनिक क्रांति समय

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई. सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 1 अंक: 239, सोमवार, 24 सितम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र

अखिलेश यादव के साथ आए मुलायम सिंह,

नई दिल्ली, एजेंसी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। वहीं, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के वादों को लेकर सरकार को घेरा। सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा के समापन पर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी थी। सपा से नाराज शिवपाल यादव के सेकुलर मोर्चा के साथ जुड़ने के कयासों के बीच मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वह अपने बेटे के साथ हैं। मुलायम सिंह यादव पूरे कार्यक्रम के केंद्र में रहे। मंच पर वह कई बार पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। वहीं, युवा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं होगी। पर साथ ही यह नसीहत करना भी नही भूले कि 'बूढों का भी सम्मान करो'। उन्होंने पार्टी में महिला भागीदारी पर भी जोर दिया। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के कार्यक्रम में मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए ही जंतर-मंतर पर साईकिल यात्रा का समापन कार्यक्रम किया गया था। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार रात को मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि, वरिष्ठ नेता आजम खान की कार्यक्रम में गैरमौजूदगी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बनी रही। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के साथ 'सोशल इंजीनियरिंग' पर खास ध्यान दिया। कार्यकर्ताओं को अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा को साथ लेकर चलने की हिदायत देते हुए उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह बात कहने के लिए यह सबसे अच्छा मौका है कि एक बार गिनती हो जानी चाहिए कि किस जाती की कितनी आबादी है। आधे-अधूरे आंकड़ो के साथ न्याय नहीं मिल सकता। इसके साथ उन्होंने यह कहने में भी देर नहीं की कि जाति के आधार पर नियुक्तियां हो रही है। अस्पतालों में भी जाति पूछने पर इलाज होता है। अखिलेश यादव ने नोटबंदी, जीएसटी, पकौड़ा बनाने और नाली की गैस से चाय बनाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने में भी कोई कमी छोड़ी। राफेल के मुद्दे पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जेपीसी के बगैर इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ सकती। इसलिए, जांच अवश्य होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान विरष्ठ नेताओं की मौजूदगी कम रही। विरष्ठ नेताओं में मुलायम के अलावा सिर्फ रामगोपाल यादव ही वहां मौजूद थे।

सार समाचार

पूर्वांचल के लिए क्या-क्या किया इसका हिसाब देने आया हूं: अमित शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान आयोजित बीजेपी की 'पूर्वांचल महाकुंभ' रैली में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पूर्वांचल में भाजपा सरकार ने क्या-क्या काम किया है, उसका हिसाब देने आया हूं। इतना ही नहीं अमित शाह ने दिल्ली के सीएम पर जमकर निशाना साधा और कहा- जब जब समय मिला देश को लूटने का काम किया। समस्या दूर किसी ने नहीं की। तीन बेटियां भूख से मर गई, सीएम देखने भी नहीं गए। वहीं, राशन कार्ड बनाने के लिए पैसे मांगे जा रहे है। अमित शाह ने एनआसी के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि दिल्ली में एनआरसी की नीति का प्रयोग होना चाहिए। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे रोहिंग्या और बांगलादेशियों को बसाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सीलिंग के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अवैध सीलिंग के लिए लोगों को रुला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

कांग्रेस पर भी लगाए आरोप

कांग्रेस पर भी आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि देश के अंदर विकास की गंगा पूर्वांचल भाई बहनों के पसीनों से बही है। देश में जितनी भी सरकारें आई 2014 के पहले उसमे 55 साल कांग्रेस की सकार रही, पूर्वांचलियों के साथ अन्नाय कांग्रेस ने किया। अमित शाह ने आगे कहा कि मोदी जी ने कहा था अगर बीजेपी की सरकार आती है तो पूर्वांचल का विकास होगा। मैं हिसाब देने आया हूं बीजेपी ने पूर्वांचल के लिए क्या-क्या किया है। बिहार, ओडिशा जैसे राज्यों का विकास देख लीजिए, पता चलेगा ये सारे राज्य किस तरह आगे आए हैं। इन सभी राज्यों के लिए कांग्रेस की सरकार पांच साल में चार लाख करोड़ रुपए देती थी और मोदी सरकरा के शासन में साढ़े चार साल में 13 लाख 80 हजार करोड़ दिया गया। इसमें 11 लाख खर्ज भी कर दिए गए हैं। इस रैली में बीजेपी के अमित शाह के अलावा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी समेत कई नेताओं ने शिरकत की।

बाल सुरक्षा मित्र लापता बच्चों के परिजनों की मदद करेंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) थानों में बाल सुरक्षा मित्र तैनात करेगा। दिल्ली के 20 पुलिस थानों को इसके लिए चिह्नित किया गया है। सुरक्षा मित्र लापता बच्चे की शिकायत लेकर आने वाले परिजनों की एफआईआर दर्ज कराने से लेकर जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। साथ ही बाल सुरक्षा मित्र स्कूल, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारे में जाकर बाल तस्करी-बाल अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी करेंगे। इन्हें आरडब्ल्यूए से भी जोड़ा जाएगा। इसमें समाजसेवी संगठनों की मदद भी ली जाएगी।

अपराध के आंकड़े थाने के चयन का आधार

आयोग की सदस्य समरा ने बताया कि पुलिस से मिले वर्ष 2017 के आंकड़ों के आधार पर थानों में पहली बार बाल सुरक्षा मित्र तैनात करने का फैसला लिया गया है। थानों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सबसे ज्यादा बच्चों के लापता होने की शिकायतें दर्ज होती हैं। इनमें दिल्ली का बाहरी इलाका भी शामिल है, जहां मजदूर वर्ग के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। काम-धंधे के लिए रोजाना बच्चों को घर पर अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसे में अनहोनी की आशंका बनी रहती है।

इन पुलिस थानों में तैनाती

नरेला, समयपुर बादली, शाहबाद डेरी, जैतपुर, विजय विहार, उत्तम नगर, संगम विहार, भलस्वा डेरी, डाबरी, खजूरी खास, करावल नगर, न्यू उस्मान पुर, महरौली, न्यू अशोक नगर, बेगमपुर, बिंदापुर, बुराड़ी, कापसहेड़ा, गोकुलपुरी और सीमापुर।

चाइल्ड हेल्पलाइन

बाल अपराध व बच्चों के गायब होने की घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1291 बना रखी है। इस पर बच्चों के गायब होने की सूचना दी जाती है। हालांकि इसके अलावा 100 नंबर और थानों में भी सीधे बच्चों के गायब होने की सूचना दी जाती है।

कानपुर से गाजियाबाद के बीच अब नहीं लेट होंगी शताब्दी और राजधानी

कानपुर, एजेंसी। कानपुर से गाजियाबाद के बीच शताब्दी, राजधानी, मेल और एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें अब नहीं फंसेंगी। अभी तक 60 से 100 वैगन लेकर गुजरने वाली मालगाड़ी के पीछे चलना इनकी मजबूरी होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 415 किलोमीटर लंबे रूट में सिर्फ तीन स्टेशनों पर ही 740 मीटर की लूप लाइनें हैं जहां मालगाड़ियां रोकी जा सकती हैं। अब रेलवे ने 14 स्टेशनों पर 1671 मीटर लंबी लूप लाइन बनाने को मंजूरी दे दी है जिसमें 93 वैगन तक की मालगाड़ियां रोकी जा सकेंगी। वर्षों से चली आ रही इस दिक्कत पर काम भी शुरू कर दिया गया है।

इसके तहत फतेहपुर से गाजियाबाद के बीच पनकी सहित 14 स्टेशनों पर लंबी लूप लाइन बनाने को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। दिल्ली से मुगलसराय के बीच रोजाना औसतन दो डबल मालगाड़ी (52 से 90 वैगन) का रैक निकलता है।

लंबी लूप लाइन न होने से मालगाड़ियों को बीच स्टेशनों पर कहीं खड़ा करके दो भागों में बांटकर चलाया जाता है। ऐसे में इसके पीछे चलने वाली शताब्दी, राजधानी एक्सप्रेस दो से तीन घंटे तक फंसी रहती हैं। इसका असर दिल्ली रूट पर दो दिन तक रहता है।

रॉफेल पर रार : रक्षा मंत्रालय का बयान- बेवजह का विवाद

रिलायंस को पार्टनर चुनने में सरकार का कोई रोल नहीं

नई दिल्ली ■ एजेंसी

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के रॉफेल डील को लेकर दिए गए बयान के बाद भारत की राजनीति में भूचाल आ गया है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर इस मामले में स्थिति स्पष्ट की है।

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के रॉफेल पर दिए बयान से मचा बवाल

अपने बयान में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान के बाद उपजा विवाद बेवजह का है। इसमें कहा गया कि फ्रांस के बयान को पूरी तरह समझने की जरूरत है। फ्रांस की मीडिया ने डील में शामिल पूर्व राष्ट्रपति के करीबियों को लेकर सवाल पूछा था, इसके बाद ही ओलांद ने कहा था कि रिलायंस का नाम भारत सरकार की तरफ से आया था। सरकार ने पहले भी यह बात कही है और फिर से अपनी पूर्व की स्थिति को दोहरा रही है कि रिलायंस डिफेंस को ऑफसेट पार्टनर चुनने में सरकार कोई हाथ नहीं है। ऑफसेट पॉलिसी की घोषणा पहली बार 2005 में हुई थी, इसके बाद कई बार इसे रिवाइज भी किया गया।

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के बयान संबंधी रपट में कहा गया है कि भारत सरकार ने रॉफेल में डिसॉल्ट एविएशन के ऑफसेट पार्टनर के रूप में किसी खास निजी कंपनी की तरफदारी की। इसकी जांच की जा रही है। बयान में कहा कि रिलायंस और डिसॉल्ट एविएशन के बीच जॉइंट वेंचर पहली बार फरवरी 2017 में सामने आया।

भाजपा का पलटवार

दलालों के रास्ते बंद होने से राहुल को दिक्कत

रॉफेल डील पर राहुल गांधी के पीएम पर निशाना साधने के बाद भाजपा ने भी पलटवार किया है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर ओछी बातें कही हैं। राहुल गांधी का बयान गैरजिम्मेदाराना है। उन्होंने डीएलएफ लैंड डील में फंसे रॉबर्ट वाड्रा को आधार बनाकर कहा कि, बहनोई के जमीन लूटने पर राहुल गांधी चुप हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब किसी पार्टी अध्यक्ष ने पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो।

पीएम पर तीखा हमला देश का चौकीदार चोर है

रॉफेल डील पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद कांग्रेस की राह और आसान होते दिख रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कान्फ्रेंस करके पीएम नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही जवाब भी मांगा है। प्रेस कांफ्रेस में राहुल गांधी ने कहा है- फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने हमारे पीएम को चोर और धोखेबाज कहा है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम को चोर कहने के अलावा हमारे देश पर सवाल उठाया है। मैं चाहता हूं कि पीएम सफाई दें। प्रधानमंत्री बताएं कि ओलांद सही है या नहीं है। राहुल ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनिल अंबानी को हजारों करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। एचएएल से ठेका छीनकर दस दिन पहले बनी रिलायंस कंपनी को ठेका दे दिया गया। रॉफेल घोटले की वजह से लोगों के दिमाग में घुस गया है कि देश का चौकीदारी चोर है। अनिल अंबानी ने कभी अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया और उन्होंने सौदा होने के कुछ ही दिन पहले कंपनी बनाई थी, फिर भी ये सौदा एचएएल से छीनकर अंबानी जी को दे दिया गया, जिन पर पहले से ही 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। राहुल ने कहा कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत सरकार के कहने पर अनिल अंबानी की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। राहुल ने रॉफेल सौदे को भ्रष्टाचार का नाम देते हुए कहा कि यह देश की रक्षा और हमारे जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रधानमंत्री पूरी तरह चुप हैं। वह एक शब्द नहीं बोले।

किसी का दबाव नहीं, खुद चुना रिलायंस को : डसाल्ट

फ्रांस सरकार के बाद अब रॉफेल विमान बनाने वाली कंपनी डसाल्ट एविएशन ने भी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि रॉफेल विमान सौदे में ऑफसेट समझौते के तहत खुद उसने ही अनिल अंबानी नीत रिलायंस समूह की कंपनी को साझेदार बनाया था। डसाल्ट की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि यह ऑफसेट समझौता रक्षा खरीद प्रक्रिया, 2016 के नियमों के तहत किया गया है। इसके तहत और मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप डसाल्ट एविएशन ने भारत के रिलायंस समूह के साथ साझेदारी का निर्णय लिया था। यह डसाल्ट एविएशन की पसंद है और सीईओ एरिक ट्रेपियर ने गत अप्रैल में एक साक्षात्कार में यह स्पष्ट भी किया था। इस साझेदारी के परिणामस्वरूप फरवरी 2017 में एक संयुक्त उपक्रम डसाल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लि. बनी। डसाल्ट एविएशन और रिलायंस ने फाल्कन और रॉफेल विमानों के कलपूर्जे बनाने के लिए नागपुर में एक सयंत्र बनाया है।

आंध्रप्रदेश: दिनदहाड़े माओवादियों ने की टीडीपी के विधायक व पूर्व विधायक की हत्या

सर्वेस्वरा राव वाईएसआरसीपी से अलग होकर टीडीपी में शामिल हुए थे।

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम में रविवार को अराकू (अजनजा) विधानसभा सीट से विधायक सर्वेश्वर राव और पूर्व विधायक एस सोमा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि दोनों नेताओं की हत्या को भाकपा (माओवादी) के सदस्यों ने अंजाम दिया है। घटना को तब अंजाम दिया गया जब विशाखापटनम से करीब 125यरू दूर अराकू के थुतांगी गांव में सर्वेश्वर राव और एस सोमा एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। तभी भाकपा (माओवादी) के सदस्यों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। सर्वेस्वरा राव वाईएसआरसीपी से अलग होकर टीडीपी में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में वे मंत्री थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें कई बार माओवादियों की ओर से हत्या की धमकियां मिलती रही हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम लिए भेज दिया है। दोनों नेताओं की हत्या के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा व्याप्त है।

अदालत ने की बिशप की जमानत अर्जी खारिज

कोट्टयम,(एजेंसी)। केरल के कोट्टयम की एक अदालत ने नन रेप मामले में गिरफ्तार हुए बिशप फ्रैंको मुलक्कल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने बिशप को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इससे पहले बिशप को दोपहर सवा एक बजे कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि शुक्रवार शाम को केरल पुलिस ने बिशप को गिरफ्तार किया था।

बिशप के वकीलों ने अदालत से यह दलील देते हुए राहत की मांग की थी कि जांच टीम ने तीन दिन की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया है। वहीं, जमानत याचिका का पुलिस ने विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच आगे बढ़ाने के लिए अभी तीन दिन की रिमांड मिलना जरूरी है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने बिशप को सोमवार दोपहर 2.30 बजे तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

शनिवार को बिशप को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। शुक्रवार रात को सीने में दर्द की शिकायत के बाद बिशप को यहां भर्ती कराया गया था। 54 साल के बिशप मुलक्कल को शुक्रवार रात को एर्नाकुलम में क्राइम ब्रांच के ऑफिस से कोट्टयम पुलिस क्लब लाया गया था। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में उन्हें 6 घंटों तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। इसी साल जून में कोट्टयम पुलिस को दी अपनी शिकायत में

कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

नन ने आरोप लगाया था कि बिशप ने एक गेस्ट हाउस में मई 2014 में उनसे रेप किया था। इसके बाद कई बार उनका यौन शोषण किया गया। नन का कहना था कि चर्च प्रशासन को बार-बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि बिशप ने सभी आरोपों को खारिज किया है। वहीं दूसरी ओर केरल में बिशप की जमानत अर्जी खारिज होने पर लोगों ने लड्डू बांटे और उनकी गिरफ्तारी की मांग की।

एक केले ने ले ली दादा-पोते की जान

शाही। केला खा रहे किशोर के गले में केला की गांठ फंस गई। दादा ने किशोर के गले में उंगली डाल कर गांठ निकालने की कोशिश की। किशोर के गले से रक्त श्राव होने लगा। किशोर की दम घुटने से मौत हो गई। पौत्र की मौत से दादा को गहरा सदमा लगा। सदमें उनकी मौत हो गई। परिवार में दो मौतें होने से घर में कोहराम मच गया। गांव दौली जवाहर लाल के ओमप्रकाश पिता 65 वर्षीय केदार के साथ पंजाब में रहते हैं। परिवार के साथ वह पंजाब में छोले भटूरे बेचते हैं। ओमप्रकाश शुक्रवार को केला घर लाए। उनके पुत्र 9 वर्षीय दिनेश केला खाने लगा। जिसकी गांठ उसके गले में फंस गई और उसका दम घुटने लगा। घर में बैठे दादा केदार ने उसकी हालत देखी तो उन्होने गले में फंसी गांठ निकालने को मुंह में उंगली डाली। कोशिश करने पर गांठ नहीं निकली। गले से रक्त श्राव होने लगा। पिता उसे डाक्टरों के पास ले गए। दिनेश की मौत हो गई। पौत्र की मौत होने से दादा को गहरा सदमा लगा। सदमे में कुछ देर बाद दादा केदार की मौत हो गई। दो लोगों की मौत होने से घर में कोहराम मच गया। ओमप्रकाश ने गांव सूचना दी। वे पंजाब से शव लेकर गांव को चल दिए।

संपादकीय

खतरों की उड़ान

मुंबई से जयपुर जाने वाली जेट एयरवेज की उड़ान में गुरुवार को जो हादसा हुआ, उसे एयरलाइंस के कारोबार में पिछले दिनों एक के बाद एक आई कई खबरों से जोड़कर देखने की जरूरत है। बेशक, ऐसा मामला पहली बार सामने आया, जब उड़ान की देख-रेख करने वाले कर्मचारी विमान में वायु दबाव यानी एयर प्रेशर का नियंत्रण बनाए रखने की प्रक्रिया अपनाना ही भूल गए, लेकिन इस मामले ने यह तो उजागर कर ही दिया कि ऐसी लापरवाहियां विमान यात्रा करने वालों के लिए किस-किस तरह के जोखिम पेश करती हैं। बात सिर्फ एक मामले की नहीं है, यात्रियों, यहां तक कि बुजुर्गों से दुर्व्यवहार की खबरें भी आती रहती हैं। ऐसे भी कई मामले आए हैं, जिनमें एयरलाइंस ने विमान में जितनी सीटें थीं, उससे कहीं ज्यादा टिकटें बेच दीं और फिर ऐन वक्त पर हवाई अड्डे पर हंगामा होता रहा। शिकायतें और भी हैं, शायद ढेरों हैं। रेलवे की प्रीमियम गाड़ियों और एयरलाइंस में कौन कितना रद्दी खाना परोस सकता है, इस पर तो जैसे दोनों में बाकायदा स्पर्द्धा ही चल रही है। यात्रा करने वालों ने भी मोटे तौर पर इन सब चीजों को अपनी नियति ही मान लिया है। लेकिन गुरुवार को जो हुआ, वह किसी भी तरह से क्षम्य नहीं है। यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, यह लापरवाही का उस हद तक चले जाना था, जहां उसे आपराधिक कृत्य करार दिया जाना चाहिए। जिस हरकत की वजह से डेढ़ सौ से ज्यादा यात्रियों की जान जोखिम में चली जाए, उसे सिर्फ लापरवाही कहकर बख्शा नहीं जा सकता। विमान में एयर प्रेशर पर नियंत्रण न होने ने सभी यात्रियों को न सिर्फ आतंकित कर दिया, बल्कि वे भयावह यंत्रणा के दौर से गुजरे। 30 से ज्यादा यात्रियों पर तो इसका कुछ ज्यादा ही गंभीर असर पड़ा। वे उस स्थिति में पहुंच गए, जिसे चिकित्सा की भाषा में बैरोट्रॉमा कहा जाता है। यह स्थिति एयर प्रेशर में तेजी से बदलाव की वजह से आती है। इसके चलते उनके नाक और कान से खून तक बहने लगा। सांस लेने में दिक्कत तो खैर सभी यात्रियों को हुई। यह तो अच्छा हुआ कि विमान को जल्द ही मुंबई हवाई अड्डे पर वापस उतार दिया गया, और किसी बड़े हादसे से यात्रियों को बचा लिया गया। यात्रियों के लिए तो यह एक यंत्रणा सा था ही, जिसने भी इसे सुना या टेलीविजन पर देखा, उसने ही इसके भय को महसूस किया। विमान यात्रा को हमारे देश में अभी भी सुविधा संपन्न वर्ग के यातायात का साधन माना जाता है, वहां भी अगर यह हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि पूरी तरह सुरक्षित कोई नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था और मध्य वर्ग के विस्तार के साथ पिछले कुछ साल में विमान यात्रियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इतनी तेजी से कि इसके लिए उपलब्ध इन्फ्रास्ट्रक्चर छोटा पड़ गया है। ऐसी खबरें भी आईं कि लगातार विमान उड़ाने का दबाव इतना ज्यादा है कि विमान चालक ठीक से पूरी नींद सो भी नहीं पाते। इस सबके खतरे हम आसानी से समझ सकते हैं। कारोबार में भारी विस्तार के बाद यह उम्मीद की जाती है कि किसी भी धंधे में लगी कंपनियां अपनी गुणवत्ता सुधारेंगी, लेकिन गुणवत्ता सुधरना तो दूर, गुणवत्ता लगातार गिर रही है और इसके साथ ही यात्रियों के जोखिम भी बढ़ रहे हैं। विमान यात्रा को नए दौर का सबसे त्वरित और आरामदेह साधन माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही इसे सुरक्षित बनाए रखना भी बहुत जरूरी है।

संघ का रूपांतरण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का ''भविष्य का भारत-संघ का दृष्टिकोण' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला का समापन हो गया। व्याख्यानमाला के माध्यम से आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने हिन्दू राष्ट्र, हिन्दुत्व, समान नागरिक संहिता, राम मंदिर, जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार और दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए, आरक्षण, जनसंख्या संतुलन जैसे अनेक अहम और विवादास्पद सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। देश के राजनीतिक क्षेत्र, अल्पसंख्यकों और खासकर बौद्धिक जगत में संघ की कार्यशैली और नीतियों को लेकर शुरू से अनेक तरह की शंकाएं रहीं हैं। यही वजह रही है कि आमंत्रित करने के बावजूद देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी और गैर भाजपा दलों के शीर्ष नेताओं ने इस व्याख्यानमाला से अपने को अलग रखा। आरएसएस ने आखिर इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, इस सवाल पर भी लोग माथापच्ची कर रहे हैं। इस आयोजन का एक अर्थ यह निकाला जा सकता है कि लोक सभा और पांच राज्यों के चुनावों से पूर्व आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत उन लोगों की शंकाओं का निवारण करना चाहते थे, जो तटस्थ मतदाता हैं, यानी किस राजनीतिक दल के पक्ष में अपना मत देना है, इसे लेकर अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। वह ऐसे मतदाताओं की शंकाओं को भी दूर करना चाहते थे, जो भाजपा को संकुचित विचारधारा वाली अलोकतांत्रिक पार्टी मानते हैं। अपने इस प्रयास में संघ परिवार कितना सफल हुआ है, यह तो आने वाला समय बताएगा। मगर यह तो कहा जा सकता है कि मोहन भागवत के कार्यकाल में संघ का रूपांतरण हो रहा है। इन्होंने ''बंच ऑफ थाट्स' पुस्तक में संकलित पूर्व सरसंघचालक एम.एस गोलवलकर (गुरुजी) के भाषणों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ''परिस्थितियोंवश व्यक्त किए गए विचार शाश्वत नहीं रहते। संघ बंद संगठन नहीं है। समय बदलता है। हमारी सोच बदलती है। गौरतलब है कि गुरुजी ''बंच ऑफ थाट्स' में ईसाइयों और कम्युनिस्टों के साथ मुलसलमानों को देश का आंतरिक शत्रु माना है। जबकि मोहन भागवत ने अपने उद्बोधन में दो टूक कहा है कि हिन्दू राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। जाहिर है उनके विचार को संघ के नजरिये में आए महत्त्वपूर्ण और व्यापक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

परिधि/विशाल तिवारी

कार्य-निष्पादन बने आधार

गुजरात में विधायकों ने अपने वेतन में 65 फीसद (70727 से 116316 रुपये) बढ़ोतरी का बिल विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करा लिया, एक अपवाद विधायक के विरोध को छोड़कर। अन्य राज्यों से तुलना करें तो माननीयों का वेतन-उत्तराखंड 2.91 लाख, तेलंगाना 2.50 लाख, झारखंड 2.25 लाख, हिमाचल 2.10 लाख, उत्तर प्रदेश 1.95 लाख, हरियाणा 1.63 लाख, जम्मू-कश्मीर 1.60 लाख, दिल्ली 1.34 लाख, असम और राजस्थान में 1.30 लाख है और पंजाब 1.15 लाख है। ऐसे समय में जब लोग पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से त्रस्त हैं, यह फैसला जनता के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। हो सकता है कि विधायकों के अपने वाजिब तर्क हों, मगर बीते सप्ताह पेट्रो उत्पादों के मूल्य वृद्धि के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान कि ''पेट्रो उत्पादों के मूल्य वृद्धि से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता' आम जनता के प्रति नेताओं के नजरिए का सैम्पल है। खैर, नीतिगत बात पर आते हैं। लगभग सभी पेशे में वेतन बढ़ाने के कुछ मानक होते हैं। कामकाज को आधार बनाया जाता है। मगर विधायिका में इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। टेलीफोन भत्ते में वृद्धि को ही लें। जिसे 4000 से बढ़ा कर 7000 रु. कर दिया। आज लगभग मुफ्त सेवा के दौर में इस भत्ते का कोई मतलब नहीं बनता। अब समय आ गया कि जनप्रतिनिधि गुणवत्ता के मानकों को तय करें, और उसी आधार पर ही वेतन बढ़े। दरअसल, महंगाई का सीधा संबंध सरकारी खर्चे जुड़ा हुआ है। साफ शब्दों में कहें तो सरकार के खजाने पेट्रो उत्पादों से मिलने वाले राजस्व से चल रहे हैं। सरकार की अपनी उत्पादकता आलस का शिकार है। कर बटोरकर देश चलाना कोई बड़ी बात नहीं। आचार्य चाणक्य से जुड़ा एक प्रसंग, जिसमें वो एक चीनी यात्री से भेंट के दौरान राज्य के तेल से जलते दीपक को बुझा कर अपने निजी दीपक को जलाते हैं। राज्य व्यवस्था द्वारा आवंटित संसाधन के दुरूपयोग न करने के संदर्भ में उत्कृष्ट उदाहरण है। मगर बात-बात में चाणक्य से प्रेरणा लेने की बात करने वाले नेता इस उदाहरण की चर्चा करना भी गंवारा नहीं समझते।

सबसे सुरक्षित साधन की गंभीर चूक

हर्षवर्धन

एविएशन यानी हवाई परिवहन एक ऐसा उद्योग है, जिसे 'जीरो एरर इंडस्ट्री' कहते हैं। इसका अर्थ है कि यहां छोटी से छोटी गलती भी अक्षम्य है, क्योंकि एक मामूली चूक भी तमाम लोगों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में मुंबई-जयपुर जेट एयरवेज की फ्लाइट में गुरुवार को जो कुछ हुआ, वह काफी गंभीर मामला है। पहली नजर में इसे मानवीय चूक कहा जा सकता है, हालांकि पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा।

आज जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, उनमें से 70 फीसदी मानवीय चूक का नतीजा होती हैं। शेष हादसे मशीनी और तकनीकी खराबी या कुछ अन्य वजहों से होते हैं। दरअसल, विमान सेवा का लगातार विस्तार हो रहा है। छोटी-छोटी जगहों तक के लिए कई उड़ानें हैं। आकलन यह है कि देश में हर महीने एक-डेढ़ लाख विमान लैंड (रनवे पर उतरना) और टेक-ऑफ (हवा में उड़ान भरना) करते हैं। फ्लाइट्स की लगातार बढ़ती संख्या ने जहाज और केबिन क्रू (पायलट और को-पायलट), दोनों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ा दिया है। यही दबाव चूक को न्योता दे रहे हैं। गुरुवार की घटना में ही यह पूछा जा रहा है कि केबिन क्रू को आराम का पर्याप्त मौका मिला था या नहीं?

> "उड़ानों की लगातार बढ़ती संख्या ने जहाज और केबिन क्रू, दोनों पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव बढ़ा दिया है। यही दबाव चूक को न्योता दे रहे हैं।"

पिछले हफ्ते एअर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी इसी तरह हादसे का शिकार होते-होते बची थी। नई दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे उस विमान में 'इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम' (आईएलएस) सहित कई महत्वपूर्ण उपकरण नाकाम हो गए थे। यह स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी, मगर पायलट ने सूझ-बूझ दिखाते हुए अनहोनी टाल दी। वह पूरी तरह से तकनीकी चूक का मसला था और कहीं ज्यादा गंभीर भी, मगर जेट एयरवेज की घटना को भी हल्के में नहीं ले सकते। आरोप है कि पायलट केबिन में मौजूद एयर प्रेशर संतुलित करने वाला स्विच दबाना भूल गया। हालांकि बाद में वह इस गलती को दुरुस्त कर सकता था, पर उसने यह भी नहीं किया। अब यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि इस सबकी वजह क्या थी, मगर एयर प्रेशर अगर काम न करे, तो स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, यह बात इस विमान के यात्रियों की तस्वीरें देखकर समझी जा सकती है। विमान में हवा का दबाव न रहने पर यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, उन्हें घबराहट हो सकती है, और उनके नाक व कान से खून निकल सकता है। अस्थमा या दमा के मरीजों के लिए तो यह स्थिति काफी घातक मानी जाती है। हृदय-रोग वालों के लिए यह जानेलवा होती है। हालांकि इस चूक की तत्काल पहचान संभव है, इसलिए विमान में ऑक्सीजन मास्क तत्काल नीचे आ गए थे।

विमान यात्रियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए विमान सेवा में कदम-कदम पर जांच-पड़ताल की जाती है। हर छोटे से छोटे उपकरण को जांचा जाता है। बावजूद इसके, नागर विमानन महानिदेशालय जैसे निगरानी तंत्र और विमानन कंपनियों के लिए यह भरोसा दिलाना काफी मुश्किल है कि कहीं कोई चूक नहीं होगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि हवाई जहाजों की उड़ान या उसका 'ऑपरेटिंग एनवायरमेंट' (संचालन से जुड़ी तमाम गतिविधियां) इंसानी कौशल और विवेक पर निर्भर करता है। पायलट को इतना अधिक वेतन इसीलिए दिया जाता है, क्योंकि उसका काम बहुत जिम्मेदारी का होता है और उसी पर यात्रियों की सुरक्षा का पूरा दारोमदार होता है।

किसी भी हवाई जहाज को उड़ान की अनुमति तमाम जांच-पड़ताल के बाद दी जाती है। मसलन, जब विमान खड़ा रहता है, तो इंजीनियर उसकी पूरी पड़ताल करते हैं। 'रिलीज' करने से पहले उसके तमाम उपकरणों की जांच की जाती है। जहाज के हर उपकरण की एक समय-सीमा तय है, जिन्हें नियत घंटे की उड़ान के बाद बदल दिया जाता है। इंजीनियर जब अपनी रिपोर्ट पायलट को सौंपता है, तो पायलट उसके तमाम उपकरणों की फिर से जांच पड़ताल करता है। टेक-ऑफ के समय पायलट और को-पायलट दी गई 'चेक लिस्ट' के अनुसार सभी जरूरी उपकरणों को फिर से परखते हैं। टेक-ऑफ के बाद भी एक 'चेक-लिस्ट' होती है, जिसमें उन उपकरणों की जांच की बात होती है, जिन्हें उड़ान भरते समय ऑन करना अनिवार्य माना जाता है। विमान के नियत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उपकरणों पर नजर रहती है। कदम-दर-कदम इस जांच-पड़ताल का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा दी जाए। बेशक केबिन क्रू इतना कुशल होता है कि उसे किसी ऐसी चेक-लिस्ट की जरूरत नहीं होती, फिर भी यह उसे इसलिए दी जाती है, ताकि कोई भूल न हो जाए। जेट एयरवेज की इस ताजा घटना में भी इन तमाम नियमों का पालन हुआ ही होगा। इंजीनियर और पायलट ने एयर प्रेशर जरूर जांचा होगा। इसीलिए अभी हमें किसी नतीजे पर पहुंचने से बचना चाहिए। भले ही विमान में कोई भी गलती एक खतरा होती है, मगर दूसरा सच यह भी है कि यदि उसके एक उपकरण ने काम करना बंद कर दिया, तो उससे कई दूसरी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। यानी यहां एक 'एरर' से दूसरी 'एरर' बनती है। इसे हम 'कंपाउंडग ऑफ फॉल्ट्स' (गलतियों का योग) कहते हैं। जैसे कि यदि पायलट कोई एक उपकरण ऑन करना भूल जाए, तो उसके ऑन न होने से दूसरे उपकरणों के काम-काज पर भी बुरा असर पड़ता है और वे भी नाकाम हो सकते हैं।

इन तमाम चुनौतियों के बाद भी एविएशन एक संगठित और व्यवस्थित उद्योग है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले हॉवर्ड के एक डॉक्टर मेरे पास आए थे। वह एक महत्वपूर्ण विषय पर शोध कर रहे थे। उनका कहना था कि कई बार डॉक्टरों की लापरवाही से ऑपरेशन के समय मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो क्यों न ऐसी कोई 'चेक-लिस्ट' बने, ताकि डॉक्टर ऐसी गलती न कर सकें। वह एविएशन के 'चेक-लिस्ट सिस्टम' को अपने पेशे में उतारना चाहते थे। मैं इसे एविएशन इंडस्ट्री की उपलब्धि मानता हूं। दूसरे क्षेत्र के लोग भी इसके सुरक्षा मानकों को स्वीकार कर रहे हैं, तभी तो हवाई जहाज यातायात का सबसे सुरक्षित साधन माना जाता है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

फिर पेपर लीक

छीना हुआ सम्मान हासिल करने का सुकून

अरुण नैथानी

पद, प्रतिष्ठा, हुनर सुकून छीनकर देशद्रोही करार दिये जाने के लांछन से मुक्त होना, निश्चय ही नया जीवन पाने जैसा है। एक ऐसे अपराध के लिए सज़ा मिलना, जो किया ही न हो; उसकी टीस कितनी भयावह होती है, ये डॉ. एस. नांबी नारायणन ही महसूस कर सकते हैं। जीवन के उत्तरार्ध में सुप्रीमकोर्ट द्वारा बेदाग घोषित किये जाने की चमक उनके चेहरे पर है। मगर महज पचास लाख का मुआवजा क्या उनके छीने गए गौरवशाली वक्त को लौटा सकता है? वह भी तब जब वे अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना को अंतिम रूप देने के करीब थे। सही मायनो में यह राष्ट्रीय हानि ही है कि हम साजिश के चलते अंतरिक्ष मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन पाने में सालों पिछड़ गए।

अब तक हमने यह जासूसी उपन्यासों व फिल्मों में देखी थी कि विदेशी खुफिया एजेंसियां महत्वपूर्ण खोज के करीब पहुंचे वैज्ञानिक को खत्म करके देश विशेष को दशकों पीछे धकेल देती हैं। नांबी नारायणन के साथ जो भयावह हुआ, उसके तार भी किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश से जुड़ते नजर आते हैं, जिसमें देश की काली भेड़ों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। नब्बे के दशक के बहुचर्चित इसरो जासूसी कांड की साजिश के सूत्र आज ढाई दशक बाद भी हाथ नहीं लगे हैं, तो इसमें संदेह की सूई महाशक्तियों की खुफिया एजेंसियों के लिए देश को ताक पर रखने वाले राजनेताओं पर उठती है। तभी तो सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बावजूद दोषी पुलिस वालों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। केरल में सरकारें बदलती रहीं और दोषी पुलिस अधिकारी खुलेआम घूमते रहे। यही वजह है कि ढाई दशक बाद मामले में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करना पड़ा है। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीमकोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस डी.के. जैन करेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे साजिश से पर्दा उठ सकेगा।

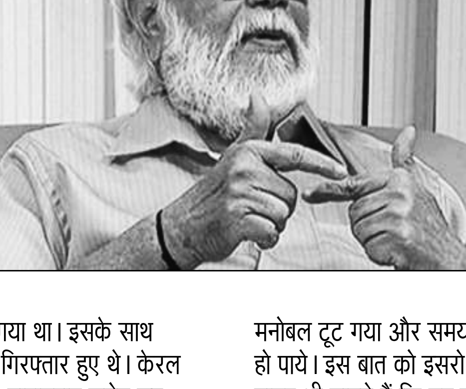

बहुचर्चित इसरो जासूसी कांड में वर्ष 1994 में मालदीव की एक महिला को कथित संवेदनशील दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया था। इसके साथ बेंगलुरू के दो व्यापारी भी गिरफ्तार हुए थे। केरल पुलिस ने इस मामले में डॉ. नारायणन समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। इस घटना का दुखद पहलू यह है कि सुप्रीमकोर्ट के फैसले से बेदाग साबित होने का इंतजार करते-करते एक वैज्ञानिक ने दम तोड़ दिया। दोनों वैज्ञानिकों पर इसरो के रॉकेट इंजन के चित्र और तकनीक दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे थे। जिस इंजन को बेचने के आरोप लगे, वो डिजाइन फ्रांस के इंजन का था, जिसको यहां भारत में फेब्रिकेट करने की कोशिश की जा रही थी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि यदि डॉ. नारायणन को यूं न फंसाया जाता और गिरफ्तार न किया जाता तो भारत क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण सालों पहले कर लेता। पुलिस की कार्रवाई से पूरी टीम का मनोबल टूट गया और समय पर लक्ष्य हासिल नहीं हो पाये। इस बात को इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉ. नायर भी मानते हैं कि यह घटना न हुई होती तो भारत बहुत पहले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन हासिल कर लेता।

बहरहाल, इस घटनाक्रम से भारत की अनमोल वैज्ञानिक प्रतिभा व्यर्थ चली गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा आम अपराधी की तरह मारा-पीटा गया। ऐसा माना जाता है कि इस साजिश में उन विदेशी ताकतों का हाथ था जो इसरो के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को अपने लिए चुनौती मानती थीं। कालांतर मामले के तूल पकड़ने के बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया और नारायणन को बरी किया गया। साल 1998 में सुप्रीमकोर्ट ने डॉ. नारायणन को निर्दोष पाया। उसके बाद उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, लेकिन आत्मसम्मान के लिए उस प्रोजेक्ट में भागीदारी नहीं की। इतनी प्रताड़ना तथा अपमानित होने के बाद ये संभव भी नहीं था।

बहरहाल, आज जब सुप्रीमकोर्ट ने उन्हें बेदाग घोषित किया है, माना कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, मुआवजा देने का आदेश दिया तथा पूरे मामले की जांच के लिए आयोग गठित करने के आदेश दिए तो डॉ. नांबी नारायणन किसी हद तक खोया सम्मान पा चुके हैं। मगर अभी यह सवाल बाकी है कि इस साजिश के पीछे कौन था? पुलिस कार्रवाई किसके इशारे पर हुई? राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका किस हद तक थी? क्या किसी महाशक्ति की खुफिया एजेंसी की भूमिका इसमें रही?

शायद आने वाले वक्त में इन सवालों का जवाब मिल जाए। बहरहाल, डॉ. नारायणन के बीते वक्त को तो लौटाया नहीं जा सकता, मगर ऐसी पुख्ता व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि भविष्य में फिर किसी राष्ट्रीय प्रतिभा को ऐसी साजिश का शिकार न होना पड़े।

तेलंगाना

पसोपेश में चुनाव आयोग

शशिधर खां

लोक सभा और विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत भाजपा नेतृत्व के दबाव से चुनाव आयोग उबर भी नहीं पाया कि बीच ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने विधानसभा भंग करके आयोग को नये फांस में डाल दिया। आयोग को अब तेलंगाना विधानसभा का चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम के साथ कराना होगा। तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने में आठ महीने से भी ज्यादा समय बचे थे। इतना पहले विधानसभा भंग होने की स्थिति का निदान संविधान में नहीं है। संविधान की धारा-324 और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के तमाम प्रावधानों को खंगालने पर भी इस सियासी संकट का हल नहीं मिलता।

इसलिए मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत को मजबूरी में उन राज्यों के साथ तेलंगाना विधनसभा का भी चुनाव कराना होगा, जिनका कार्यकाल कायदे से नवम्बर-दिसम्बर में समाप्त हो रहा है। इस स्थिति के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं था। लेकिन जब सिर्फ निहित राजनीतिक स्वार्थवश तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने पैदा कर दी। इसलिए चुनाव आयोग को कहना पड़ा कि उन चार राज्यों के साथ चुनाव कराया जा सकता है, जहां साल के अंत में चुनाव होना तय है। चुनाव आयोग को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2002 में इस संबंध में दिए गए दिशा-निर्देश का पालन करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सदन भंग होने की स्थिति में ''पहले अवसर' में ही चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि कार्यवाहक सरकार सत्ता में बने रहकर उसका लाभ नहीं उठा सकती। ओपी रावत ने कहा कि कोई भी विधानसभा भंग करके छह महीने तक कार्यवाहक सरकार के रूप में सत्ता पर काबिज नहीं रह सकता। यह बात रावत ने सात सितम्बर को ही स्पष्ट कर दी, जब तेलंगाना से आई समय पूर्व चुनाव की मांग पर दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक हुई। रावत ने कहा कि विधानसभा समय पूर्व भंग किए जाने की तारीख से छह महीने के अंदर हर हाल में चुनाव कराना है, ताकि नई विधानसभा गठित हो। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुसार चुनाव आयोग को विधानसभा भंग होने के बाद तत्काल चुनाव प्रक्रिया शुरू कर देनी है। तेलंगाना सरकार के अधीन कार्यरत मुख्य निर्वाचन अधिकारी रजत कुमार ने भी रिपोर्ट दे दी कि विधानसभा चुनाव इसी वर्ष कराया जा सकता है। ऐसा करना चुनाव आयोग की मजबूरी है और इस फांस में मुख्य चुनाव आयुक्त को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक स्वार्थवश डाला है। चुनाव आयोग कार्यकाल समाप्त होने तक चुनाव स्थगित नहीं कर सकता।

चुनाव आयोग के पास धारा-324 के अंतर्गत संविधान से चुनाव से संबंधित संपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव आयोग चाहे तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके असमय चुनाव थोपने के लिए जवाब-तलब कर सकता है। संविधान किसी मुख्यमंत्री को मनमाने तरीके से किसी भी समय विधानसभा भंग करने की इजाजत नहीं देता। विशेष परिस्थिति में भी सिर्फ छह महीने का ही प्रावधान है, जब सत्तारूढ़ पार्टी अल्पमत में आ जाए और वैकल्पिक सरकार गठन का विकल्प न हो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत में थे और विधानसभा का कार्यकाल लोक सभा चुनाव के समय ही 2019 में समाप्त होने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी भी वही चाहते थे, जिसका अप्रत्यक्ष दबाव चुनाव आयोग पर लगातार बढ़ रहा था कि लोक सभा के साथ ही विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए। रावत ने अगस्त के अंतिम सप्ताह में तमाम दवाब चर्चाओं को विराम देने के लिए अपनी फांस बाहर निकाली कि मौजूदा परिस्थिति में साथ-साथ चुनाव का कोई चांस नहीं। इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और कम-से-कम पांच धाराओं में फेरबदल किए बगैर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते। विधि आयोग के अयक्ष जस्टिस बलवीर सिंह चौहान अपना कार्यकाल समाप्त होते-होते 30 अगस्त को कह गए कि इस पर अभी और चर्चा की जरूरत है। जस्टिस चौहान ने भी कहा कि संविधान संशोधन किए बिना एक साथ चुनाव कराना संघीय ढांचे से छेड़छाड़ होगा। आयोग ने अगर चुनाव टाला तो, ''महत्वाकांक्षी' मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, इसलिए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 2002 दिशा-निर्देशों के आलोक में ही तेलंगाना में चुनाव प्रक्रिया तत्काल शुरू कर दी। तेलंगाना से नये संवैधानिक संकट आने शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग की टीम 11 सितम्बर को जब हैदराबाद पहुंची, उसी दिन मुख्य विपक्षी दल तेलुगू देशम पार्टी, कांग्रेस और सीपीआई नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर डाली। देखना है, राज्य के भविष्य की खातिर चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है?

रुपए की कमजोरी के चलते गाड़ियों के दाम बढ़ा सकती हैं टोयोटा, मर्सिडीज बेंज

नई दिल्ली।

लगातार कमजोर होते रुपये के चलते जापान की कार निर्माता कंपनी टोयोटा और जर्मनी की कार कंपनी मर्सिडीज-बेंज देश में अपनी कारों की कीमत में इजाफा करने पर विचार कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 72 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। इससे वाहन कंपनियों की चिंताएं बढ़ी हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उप प्रबंध निदेशक एन. राजा ने कहा, 'मौजूदा समय में हम उच्च लागत को झेल रहे हैं। हालांकि रुपये में और गिरावट के चलते आने वाले दिनों में ऊंची लागत को और संभाल पाना मुश्किल होगा। हमें इस लागत को ग्राहकों तक हस्तांतरित करना होगा और इसके लिए हमें कीमतों में इजाफा करना होगा।' टोयोटा किर्लोस्कर, भारत के किर्लोस्कर समूह और जापान के टोयोटा समूह का संयुक्त उपक्रम है। राजा ने कहा कि कंपनी अभी भी विशेष कलपुर्जों के लिए आयात पर निर्भर है। भले ही इसने पिछले कई सालों में अधिकतर कलपुर्जों में स्थानीय सामान की हिस्सेदारी बढ़ायी हो। टोयोटा किर्लोस्कर देश के भीतर कई तरह के वाहन बेचती है जिसमें स्थानीय तौर पर बनी हैचबैक कार इटियॉस लीवा से लेकर आयातित एसयूवी लैंड क्रूजर तक शामिल हैं। हालांकि कंपनी के निर्यात बढ़ाने के सवाल पर राजा ने कहा कि कंपनी की भविष्य की योजनाओं पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मर्सिडीज-बेंज इंडिया के उपाध्यक्ष (बिक्री एवं विपणन) माइकल जॉप का भी मानना है कि रुपये की गिरती हालत कंपनी के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा, 'हमने विकास के आधार पर पिछले दो से तीन माह में पहले ही कीमतों में कुछ वृद्धि लागू की है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में और गिरावट (रुपये) देखी गई है जो कि चिंता का विषय है। ऐसे में हम इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और यह समस्या और गहराती है तो कीमत बढ़ाना अपरिहार्य हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कंपनी ने इसी महीने कीमतों में चार प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की थी, ताकि बढ़ी लागत के प्रभाव को कम किया जा सके। इससे पहले इसी महीने होंडा कार्स ने कहा था कि रुपये की गिरावट की वजह से उसे एक बार अपने वाहनों के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं।- एजेंसी

बीएसएनएल ने 5जी सेवाओं की शुरुआत के लिए सॉफ्टबैंक, एनटीटी के साथ किया करार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने देश में 5जी और इंटरनेट से जुड़ी प्रौद्योगिकियों को शुरु करने के लिए जापान की सॉफ्टबैंक और एनटीटी कम्युनिकेशन्स के साथ करार किया है। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने 'पीटीआई-भाषा' से एक साक्षात्कार में कहा, 'हमने भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के संबंध में सॉफ्टबैंक और एनटीटी कम्युनिकेशन्स के साथ करार किया है। इस समझौते के तहत हम समाधान, स्मार्ट शहरों के लिए, तलाशेंगे।'

उन्होंने कहा कि बीएसएनएल के अधिकतर प्रतिद्वंद्वी अब भी अपनी 4जी सेवाओं के जरिए ही रुपये कमाना चाह रहे हैं, इसलिए अग्रणी कंपनियां 5जी की शुरुआत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की ओर देख रही हैं। श्रीवास्तव ने कहा, ÷हमें हमारे मंत्री (मनोज सिन्हा) की ओर से की गयी पहल का लाभ हुआ है। उन्होंने 5जी के लिए वैश्विक स्तर पर कई बैठकें की है। हमने उन अवसरों को भुनाते हुए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के लिए करार किया है।'

दूरसंचार मंत्री सिन्हा ने कहा है कि भारत में अन्य प्रमुख देशों के साथ ही 5जी सेवाओं की शुरुआत होगी। श्रीवास्तव ने कहा, 'विदेशी बाजार में 3जी सेवाओं की शुरुआत के सात साल बाद यह भारत में शुरू हो सका था। 4जी सेवाएं भी चार साल की देरी से शुरू हुई लेकिन भारत में 5जी सेवाओं की शुरुआत आईटीयू द्वारा मानक तय किये जाने के साथ ही 2020 में होगी।'

उन्होंने कहा बीएसएनएल इस बात पर गौर कर रहा है कि देश में किन क्षेत्रों में 5जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉफ्टबैंक के साथ करार के तहत बीएसएनएल जापानी कंपनी के उपग्रहों का इस्तेमाल तेज गति की इंटरनेट सेवाओं को पहुंचाने के लिए करेगा। बीएसएनएल ने 5जी तंत्र विकसित करने के लिए नोकिया और सिस्को के साथ भी करार किया है।

गंगा सफाई योजना के तहत सीवरेज ढांचे पर खर्च होंगे 18,000 करोड़: गडकरी

नयी दिल्ली। गंगा को साफ- सुथरा और स्वच्छ बनाने के प्रयासों के तहत सरकार की बड़ी प्राथमिकता सात राज्यों में सीवरेज ढांचा तैयार करने की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि सरकार सात राज्यों में कुल 18,000 करोड़ रुपये की लागत 115 दूषित जल शोधन संयंत्र लगा रही है। गडकरी ने कहा कि इसके अलावा नदी किनारों के विकास तथा गंगा पर राष्ट्रीय जलमार्ग- एक के विकास के जरिये कार्गो परिवहन को प्रोत्साहन की योजनाएं भी चल रही हैं। गडकरी ने कहा, ''गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सरकार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और दिल्ली में 17,876.69 करोड़ रुपये की लागत से 115 दूषित जल शोधन संयंत्र लगा रही है। उन्होंने बताया कि ये 115 परियोजनायें गंगा नदी के विकास के लिए लगाई जाने वाली कुल 240 परियोजनाओं का ही हिस्सा हैं। मंत्री ने बताया कि इनमें से 27 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो गई हैं।

छोटे उद्योगों को प्राथमिकता से मिले उधार

नई दिल्ली ।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यातकों और छोटे उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर उधार देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को एक पत्र लिखते हुये कहा है कि इस संबंध में बैंकों को विशेष निर्देश दिये जाने चाहिए। प्रभु ने जेटली को लिखे एक पत्र में निर्यातकों के लिये उधारी में गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे निर्यातकों और छोटे उद्योगों के लिये पूंजी का संकट पैदा हो गया है और निर्यातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि निर्यातकों को दिये जाने वाले ऋण को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। उधारी में कमी आने से निर्यातकों विशेषकर छोटे उद्योगों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार इस वर्ष में 22 जून तक लंबित निर्यात उधारी 22 हजार 300 करोड़ रुपए रह गयी है जबकि इससे पिछले वर्ष 23 जून को यह आंकड़ा 39 हजार करोड़ रुपए था। इसके अलावा 30 मार्च 2018 को लंबित निर्यात उधारी 28 हजार 300 करोड़ रुपए दर्ज की गयी थी। प्रभु ने वित्त मंत्री से निर्यात उधारी को बैंकों की प्राथमिक श्रेणी में रखने का अनुरोध करते हुये कहा कि इसके लिये बैंकों को उचित निर्देश जारी किये जाने चाहिए जिससे निर्यातकों और छोटे उद्योगों को समय पर पूंजी मिल सके। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी।इस बीच भारतीय निर्यातक संगठन ने कहा है कि हालांकि सरकार ने निर्यातकों के लिये ऋण की सीमा में वृद्धि दी है लेकिन यह भी एक समस्या बन गयी है। पूरी तरह से सटीक लेन देन करने वाले निर्यातको को भी ऋण नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष में अगस्त तक निर्यात 221 अरब डालर तक पहुंच चुका है जबकि पिछले वित्त वर्ष निर्यात का आंकड़ा 303 अरब डालर का रहा था। सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष योजनाएं चलायी है और नये बाजारों तथा नयी वस्तुओं पर जोर दिया जा रहा है।

सेबी ने एफपीआई के लिए संशोधित केवाईसी नियम जारी किय

नई दिल्ली।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को राहत देते हुए सेबी ने ऐसी संस्थाओं के लिए संशोधित केवाईसी नियम और अहर्ता शर्तें जारी की है एफपीआई के कुछ वर्गों के लिए लाभ प्राप्तकर्ता स्वामियों की सूची तैयार करना और उस जानकारी को नियामक को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। पहले से पंजीकृत एफपीआई को इसके लिए छह माह का समय दिया गया है। श्रेणी-2 व 3 के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का वर्गीकरण उनके साथ जुड़े जोखिमों के आधार पर किया गया है। आरबीआई के पूर्व उप गवर्नर एच आर खान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश और लोगों की प्रतिक्रिया पर गौर करने के बाद संशोधित केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) नियम जारी किये गए हैं।

सोना 250 रुपए टूटा, चांदी की चमक हुई तेज

नई दिल्ली। स्थानीय आभूषण कारोबारियों की मांग में गिरावट के बीच कमजोर वैश्विक रुख से दिल्ली सर्राफा बाजार में शनिवार को सोना 250 रुपए गिरकर 31,450 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। हालांकि, सिक्का निर्माताओं एवं औद्योगिक इकाइयों की छिटपुट मांग से चांदी 70 रुपए बढ़कर 38,150 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। बाजारसूत्रों ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार मोर्चे पर बढ़ते तनाव से डॉलर में मजबूती आने से वैश्विक स्तर पर कीमती धातु में गिरावट रही। इसका असर यहां स्थानीय सर्राफा बाजार में भी देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में सोना 0.68 प्रतिशत गिरकर 1,198.70 डॉलर प्रति औंस रहा और चांदी 0.38 प्रतिशत गिरकर 14.25 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। सूत्रों ने कहा कि स्थानीय बाजार में आभूषण कारोबारियों और खुदरा विक्रेताओं की ओर से कमजोर मांग से भी सोने में गिरावट रही। राष्ट्रीय राजधानी में, 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 250-250 रुपए गिरकर क्रमश- 31,450 रुपए और 31,300 रुपए प्रति दस ग्राम पर टिका। शुक्रवार को सोना 50 रुपए मजबूत हुआ था। हालांकि, 8 ग्राम वाली गिन्नी 24,500 रुपए प्रति इकाई पर ही टिकी रही। चांदी हाजिर 70 रुपए मजबूत होकर 38,150 रुपए प्रति किलोग्राम और साप्ताहिक डिलीवरी 15 रुपए बढ़कर 37,590 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बोली गई। हालांकि, चांदी सिक्का लिवाल और बिकवाल 72,000 रुपए और 73,000 रुपए प्रति सैकड़ा के पूर्व स्तर पर रहा।

दीपावली पर दस हजार परिवारों के घर का सपना होगा पूरा

औरंगाबाद। बिहार के औरंगाबाद जिले में दस हजार से अधिक गरीब और बेघर परिवारों को दीपावली से पूर्व नई आशियाने की खुशियां मिलने वाली हैं । जिलाधिकारी राहुल रंजन महिवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दस हजार से अधिक गरीब और बेघर परिवारों को दीपावली के पूर्व नए पक्के मकान में गृह प्रवेश करा दिया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मुकम्मल तैयारी की जा रही है । उन्होंने बताया कि आवास योजना के तहत निर्माणाधीन पक्के मकानों को शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों तथा लाभुकों को विशेष निर्देश दिए गए हैं । इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत दी जाने वाली राशि को त्वरित गति से लाभुकों के बीच वितरित करने की पहल की गई है। महिवाल ने बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष 2017 - 18 और 2018 - 19 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 22 हजार से अधिक नए पक्के मकान बनाए जाने की योजना है और इन सभी मकानों को मार्च 2019 के पूर्व हर हाल में पूरा करा लिया जाएगा । इसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन मकानों के निर्माण की गति पर विशेष रूप से नजर रखने को कहा गया है और इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि लाभुकों को मकान के निर्माण में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो ।

एमएसपी में इजाफा, कृषि ऋण माफी की वजह से ग्रामीण मांग के गति पकड़ने की संभावना : रिपोर्ट

नई दिल्ली।

अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, कृषि ऋण माफी और ग्रामीण व्यय में बढ़ोत्तरी के साथ ही आने वाले महीनों में ग्रामीण मांग के तेजी पकड़ने के आसार हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की एक शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निवेशकों को उपभोग आधारित कंपनियों में निवेश करना चाहिए। बीओएफएएमएल ने कहा, एमएसपी में इजाफा और कृषि ऋण माफी की बदौलत हम उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रामीण मांग 2019 के आखिर तक गति पकड़ लेगी। असामान्य मानसून की वजह से फसल की तुलना में उत्पादन की गति धीमी रह सकती है लेकिन न्यूतनम समर्थन मूल्य में वृद्धि से कृषि उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वित्त वर्ष में बागवानी से भी आय में इजाफ़े की संभावना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच फलों और सब्जियों के दाम में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जिसमें पिछले साल 2.1 फीसदी की कमी आई थी। बीओएफएएमएल के मुताबिक सर्दियों में खरीफ फसलों की कटाई के समय किसानों की आय में 14.6 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण दबाव की वजह से हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में किसान आंदोलनों की शुरुआत हुई। उसके मुताबिक आने वाले महीनों में सरकार ग्रामीण व्यय में इजाफा कर सकती है।

9 सार्वजनिक कंपनियों की संपत्ति बेचेगी सरकार

नई दिल्ली ॅ

वित्तीय संकट से जूझ रही 9 सरकारी कंपनियों की संपत्ति बेच दी जाएगी। केन्द्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन सरकारी कंपनियों में एयर इंडिया हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड भी शामिल है। मसलन सरकार ने रणनीतिक बिक्री के लिए चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी सेन्ट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज (सीपीएसई) की कुछ संपत्तियों की पहचान की है। इनमें जमीन और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। जानकारी में रहे कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए रणनीतिक बिक्री एवं सार्वजनिक कंपनियों में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री से 80,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में हिस्सेदारी का विनिवेश करके 9,220 करोड़ रुपये जुटाए हैं। पिछले साल सरकार ने विनिवेश के जरिए 1.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई थी। इन सीपीएसई की संपत्तियों की बिक्री सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की चुनिंदा कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश से पहले करेगी। कुल 24 सीपीएसई को रणनीतिक बिक्री के लिये सैद्धांतिक मजूंरी मिली है। सरकार ने इनमें से 9 कंपनियों की कुछ परिसंपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें अलग-अलग किया जाएगा और फिर अलग-अलग इनका निपटान किया जाएगा।

55 हजार मुखौटा कंपनियों का पंजीयन रद्द : चौधरी

मुंबई।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि धन के अवैध प्रवाह को रोकने के प्रयासों के दूसरे चरण (2018-19) में करीब 55 हजार मुखौटा कंपनियों का निबंधन रद्द कर दिया गया है और इन कई कंपनियों को नोटिस जारी कर उनकी जांच की जा रही है। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय पहले चरण (2017-18) में दो साल या इससे अधिक समय तक वित्तीय जानकारियां या वार्षिक रिटर्न दायर नहीं करने वाली 2.26 लाख से अधिक मुखौटा कंपनियों का निबंधन रद्द कर चुका है।कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स के चौथे वार्षिक सम्मेलन से इतर यहां संवाददाताओं से कहा कि जहां तक मुखौटा कंपनियों का सवाल है, पहले चरण में हमने प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली करीब 2.26 लाख कंपनियों का निबंधन रद्द कर दिया है। इनमें से 400 से अधिक कंपनियां एक कमरे से संचालित हो रही थीं। पी.पी. चौधरी ने कहा कि दूसरे चरण में हम पहले ही करीब 55 हजार कंपनियों का पंजीयन रद्द कर चुके हैं और कई कंपनियां जांच के घेरे में हैं। चौधरी ने कहा कि सरकार धन का हेर-फेर, मादक पदार्थों का वित्त पोषण या किसी अन्य अवैध गतिविधियों के द्वारा कॉरपोरेट ढांचे का दुरुपयोग होने देना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) एवं अन्य प्रवर्तन प्राधिकरण मुखौटा कंपनियों के मामले की जांच कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जा रही है।

केजी बेसिन में 72 गैस कुएं विकसित करेगा ONGC, ईएसी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनी ओएनसीजी को कृष्णा-गोदावरी बेसिन में 72 कुओं को विकसित करने के लिये अतिरिक्त खुदाई के वास्ते हरित मूंजरी मिल गयी है. पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने यह मंजूरी दी. ओएनजीसी ने आंध्र प्रदेश के कृष्णा, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में 72 कुओं को विकसित करने के लिये उनमें अतिरिक्त खुदाई से संबंधित परियोजनाओं के लिये पर्यावरण मंत्रालय के समक्ष प्रस्ताव भेजा था. ईएसी ने 30 अगस्त को आयोजित बैठक के ब्योरे में कहा कि ईएसी ने विचार-विमर्श के बाद परियोजना के लिये पर्यावरण मूंजरी की सिफारिशों को अनुमति दे दी है. यह मूंजरी नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन है. पर्यावरण मंजूरी देते समय समिति ने कहा कि कुओं के अन्वेषण, उत्पादन, भंडारण और रखरखाव के दौरान यदि मीथेन गैस का उत्सर्जन होता हो तो इंफ्रा-रेड कैमरे या उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके इसकी निगरानी की जानी चाहिये. यह समिति द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक है. समिति ने कहा कि प्रत्येक कुएं के लिये कुल 4.5 एकड़ भूमि की जरूरत होगी. परियोजना की अनुमानित लागत 792 करोड़ रुपये है.

आर्थिक आंकड़े और वैश्विक संकेत तय करेंगे शेयर बाजार की चाल

मुबई (एजेंसी)।

लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट में रहने वाले घरेलू शेयर बाजार की चाल आगामी सप्ताह वैश्विक संकेतों के अलावा आर्थिक आंकड़े तथा रुपये और कच्चे तेल के उतार-चढाव से तय होगी। बीते सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 1,249.04 अंक की साप्ताहिक गिरावट के साथ 36,841.60 अंक पर और एनएसई का निफ्टी 372.10 अंक लुढ़ककर 11,143.10 अंक पर आ गया।

दिग्गज कंपनियों की तरह छोटी और मंझोली कंपनियों में भी बिकवाली का भारी दबाव रहा और बीएसई का मिडकैप 754.34 अंक की साप्ताहिक गिरावट में 15,595.63 अंक पर और स्मॉलकैप 907.83 अंक लुढ़ककर 15,763.10 अंक पर आ गया। बीते सप्ताह कारोबार के अंतिम दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की खस्ता हालत को लेकर फैली अफवाह से कंपनियों को सबसे अधिक घाटा उठाना पड़ा और बाजार पूंजीकरण में कई लाख करोड़ रुपये की कमी आयी।

अगले सप्ताह भी एनबीएफसी को लेकर निवेशक सतर्कता बरत सकते हैं। हालांकि इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मीडिया में बयान देकर निवेशकों को अपनी मजबूत आर्थिक स्थिति के प्रति आश्वस्त करने की कोशिश की है लेकिन इसका असर अगले सोमवार को बाजार खुलने पर ही पता लग पायेगा। इस हलचल के बीच दिवालिया हो चुकी कंपनी आईएलएंडएफसी के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश बावा ने शुक्रवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

इसके साथ ही आगामी सप्ताह गुरुवार को सितंबर का वायदा कारोबार समाप्त होने वाला है, जिसका असर बाजार पर दिखेगा। सरकार शुक्रवार को अगस्त के वित्तीय घाटे के आंकड़े जारी करेगी। भारतीय मुद्रा डॉलर के टूटने से बीते सप्ताह आखिरी दो दिन मजबूती में रही है और अगले सप्ताह इसके रूख से निवेशकों का रूझान प्रभावित होगा। कच्चे तेल के बाजार पर भी निवेशकों का ध्यान है। इन सबके बीच वैश्विक मंच पर 25 और 26 सितंबर को होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर निवेशकों की नजर होगी।

ऐसा अनुमान है कि फेड रिजर्व ब्याज दर में इस बार 25 आधार अंकों की बढोतरी कर सकता है, जिससे शेयर बाजार पर दबाव आ सकता है। अमेरिका और चीन के बीच विवाद भी कारोबारी धारणा को कमजोर हुये है। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान सेंसेक्स की 30 में से मात्र पांच कंपनियों को हरे निशान में जगह मिल पायी। शेष सभी 25 कंपनियां गिरावट में रहीं। आईटी कंपनी विप्रो के शेयरों में सबसे अधिक 2.18 फीसदी की साप्ताहिक तेजी रही।

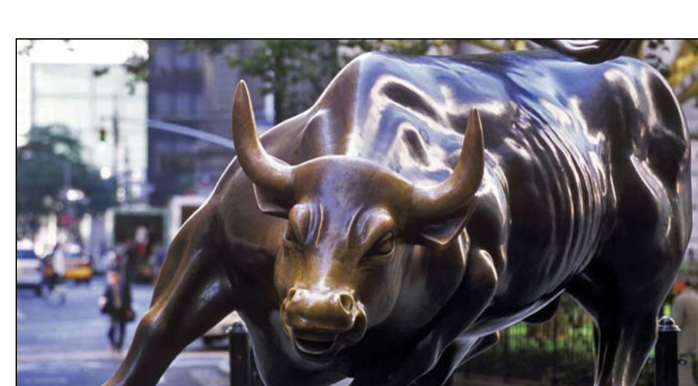

इसके साथ ही टीसीएस में 1.96, टाटा स्टील में 1.50, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.70 और पावर ग्रिड में 0.05 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गयी। सबसे अधिक घाटा इस अवधि में यस बैंक को हुआ। बैंक के शेयरों में 29.73 फीसदी की साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गयी। इसके अलावा टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयरों के भाव 8.50, भारतीय स्टेट बैंक के 7.01, टाटा मोटर्स के 6.10, इंडसइंड बैंक के 5.97, एक्सिस बैंक के 5.79, अदानी पोटर्स के 4.75, एचडीएफसी के 4.72, कोटक बैंक के 4.67, सन फार्मा के 4.45, एनटीपीसी के 4.37, इंफोसिस के 3.93, आईसीआईसीआई बैंक के 3.15, एचडीएफसी बैंक के 2.97, भारती एयरटेल के 2.93, बजाज ऑटो के 2.87, रिलायंस के 2.87, वेदांता के 2.46, एशियन पेंट्स के 2.10, एल एंड टी के 2.00, आईटीसी के 1.04, हीरो मोटोकॉर्प्स के 0.67, कोल इंडिया के 0.60 और भहदुस्तान यूनीलीवर के 0.52 प्रतिशत लुढ़क गये।

सूरत। सचिन कनसाड़ में जय अंबे ग्रुप द्वारा गणेश पूजा और भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ जिसके बाद समाज कल्याण संघ गुजरात प्रदेश अध्यक्ष लल्लन बिंद, कोषाध्यक्ष अमरजीत निषाद, सूरत जिला अध्यक्ष संजय बिंद, संगठन मंत्री स्यामसुन्दर बिंद, डिंडोली साखा अध्यक्ष समरबहादुर बिंद, शोरबहादुर बिंद, राजबहादुर बिंद सहित आसपास के लोगों ने भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण किया।

हीरा दलाल के साथ 3 लाख की हीरे की धोखाधडी

सूरत। शहर के कापोद्रा में गायत्री सोसायटी में ऑफिस चलानेवाले हीरा व्यापारी द्वारा दलाल के पास से 3 लाख रूपए की कीमत का तैयार हीरे का पैकेट लेकर ठगी करने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज हुई है।

कापोद्रा पुलिस सूत्रों के अनुसार वराछा एल.एच. रोड सपना सोसायटी निवासी रसिक रमण पानसुरिया हीरा दलाली का कार्य करते हैं। रसिक को गत 1 सितम्बर को कापोद्रा गायत्री सोसायटी में ऑफिस चलानेवाले हीरा व्यापारी मोटा वराछा, आनंद वाटिका निवासी दीपक मधु देवाणी ने अपनी ऑफिस में हीरा लेकर बुलाया था। जिससे रसिक ने 3 लाख रूपए की कीमत का 9 कैरेट 72 सेन्ट के तैयार हीरे का पैकेट लेकर पैसा देता हूं आप बैठो ऐसा कहकर हीरे का पैसा नहीं देकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने रसिक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

गणपति बप्पा मोरिया.....

मानसरोवर मित्र मंडल।

श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा वड़ापाव का वितरण किया गया। श्री श्याम मंदिर वी.आई.पी रोड़ वेसु।

श्री श्याम सेवा ट्रस्ट द्वारा वड़ापाव का वितरण किया गया। श्री श्याम मंदिर वी.आई.पी रोड़ वेसु।

अंबाजी में माता के भक्तों की भीड़ बरकरार रूप से जारी

पांचवें दिन भक्तों की भारी भीड़ : ४ दिन में १५ लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके है : भव्य तैयारियां जारी

पालनपुर। तीर्थयात्रा और शक्तिपीठ अंबाजी में सात दिवसीय पूर्णिमा मेले के रविवार को पांचवें दिन बारिश का माहौल होने के बावजूद भी भक्ति और श्रद्धा के साथ माता के भक्तों की भीड़ बरकरार रही। अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा की गई सुविधाओं की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। देवस्थान ट्रस्ट के चेयरमैन संदीप सागले की सूचना और मार्गदर्शन के अनुसार मेले में यात्रियों को आसानी से सभी सुविधा मिल रही है। अंबाजी मंदिर परिसर और अंबाजी जिला प्रशासन और ट्रस्ट द्वारा रोशनी और लाइटींग की सुंदर व्यवस्था की वजह से भव्यता और सुंदरता में चार चांद लग गया है। २५ सितम्बर को पूर्णिमा मेला का अंतिम दिन रहेगा। ३० लाख से ज्यादा श्रद्धालु सात दिन में पहुंचते है। चौथे दिन चार लाख ५४ हजार से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन का लाभ लिया। रविवार को पांचवें दिन भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। गत दिन चौथे दिन तीन लाख ६६ हजार ९६३ फूड पैकेट का वितरण किया गया। चार दिन की कुल आय एक करोड़ चार लाख ७३ हजार तक पहुंच गई है। जिसमें सोने का उपहार भी शामिल है। माता के दर्शन के लिए लंबी लाइन बरकरार रही है। रास्तों पर जिला प्रशासन और अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट द्वारा व्यापक सुविधाएं की गई है। माता के भक्तों द्वारा रास्तों पर जगह-जगह चाय-पानी, नास्ता, आराम, खाने की व्यापक सुविधा की गई है। अंबाजी मेला पर कलेक्टर संदीप सागले की सीधी नजर रही है। मेले को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां की गई हैं। शक्तिपीठ आरासुरी में माता अंबे का अंबाजी मानते है। आरासुर में माताजी के हृदय का और अर्बुदाचल आबु पर्वत पर होठ का हिस्सा गिरा होने का माना जाता है अभूतपूर्व संख्या में भक्त पहुंच रहे है। रविवार को भी भक्त पहुंच गये है। माताजी के दर्शन करने के लिए लंबी लाइनें लग गई। घंटों तक लोग लाइन में खड़े रहे। दूसरी तरफ पैदल यात्री संघ भी अभूतपूर्व संख्या में रास्तों में पहुंच रहे है। अंबाजी देवस्थान द्वारा भी रास्तों पर यात्रियों के लिए कई स्थलों पर पक्का सेड बनाये गये है। मेला के अवसर पर ट्रस्ट द्वारा ८१ जगह पर वोटरप्रूफ विशाल शेड बनाये गये हैं। अंबाजी मंदिर में लाइन खड़े रहे दर्शनार्थियों को स्वयंसेवकों द्वारा जल सेवा दी जा रही है।

उत्तर गुजरात में भारी बारिश जारी रही : भिलोडा में ७ इंच से ज्यादा

बारिश से बड़ी संख्या में वाहनों और लोग शामलाजी हाइवे पर फंस गये हिम्मतनगर में पांच इंच से ज्यादा और इडर में चार इंच से ज्यादा बारिश

अहमदाबाद। उत्तर गुजरात में भारी बारिश का दौर रविवार को जारी रहा। अरवल्ली के भिलोडा में ७ इंच से भी ज्यादा होने से चारों तरफ जल भराव की स्थिति देखने को मिली थी। चारों तरफ पानी भर जाने से लोग भारी परेशानी में आ गये। मोडासा-शामलाजी हाइवे पर भी पानी फिर से आ गया। भिलोडा में जनजीवन संपूर्ण तरीके से ठप हो गया। हाथमती नदी दो किनारे से बहने लगी। भारी बारिश की वजह से बड़ी संख्या में वाहनों और लोग शामलाजी हाइवे पर फंस गये। अरवल्ली जिले में बारिश दर्ज की गई। अभी भारी बारिश गुजरात में जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विभाग द्वारा इसकी चेतावनी भी जारी की गई है। साबरकांठा, हिम्मतनगर, इडर सहित के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण चारों तरफ पानी भर गया। हिम्मतनगर में घंटों में ही पांच इंच से ज्यादा बारिश हुई है। जबकि इडर में चार इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मेहसाणा में भी कम समय में ही दो इंच से ज्यादा बारिश हुई है उत्तर गुजरात के अलावा कच्छ-मांडवी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई होने की रिपोर्ट मिली है। हाल में जहां पूर्णिमा मेला चल रहा है यह धार्मिक स्थल अंबाजी में भी उल्लेखनीय बारिश हुई है। हालांकि इसकी वजह से भक्तों पर कोई असर नहीं हुआ है। भक्तों की भीड़ कायम रही है। हिम्मतनगर-इडर हाइवे पर भी पानी फिर से आ गया। दो घंटों में ही चार इंच से ज्यादा बारिश दर्ज होने पर रास्ते पर कई वाहन फंस गये। सरखेज हाइवे पर भी भारी बारिश हुई होने की रिपोर्ट मिली है और यहां भी पानी फिर से आ गया। मेश्वो नदी दो किनारे से बहने लगी है। शामलाजी के निकट मेश्वो नदी पर पर मेश्वो बांध भी ओवरफ्लो होने के निकट पहुंच गई है। रविवार को लगातार दूसरे दिन गुजरात के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश जारी रही। यहां उल्लेखनीय है कि, शनिवार को उत्तर और मध्य गुजरात में कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई। राज्य के ६० से ज्यादा तहसीलों में उल्लेखनीय बारिश हुई। शनिवार को कवांट, मोडासा, दाहोद, गांधीनगर, साबरकांठा, हिम्मतनगर, जांबुघोडा, छोटाउदेपुर, नसवाडी, बोडेली, गरबाडा में भारी बारिश हुई। रविवार को उत्तर गुजरात में उल्लेखनीय बारिश हुई। विशेष करके अरवल्ली के भिलोडा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मोडासा-शामलाजी हाइवे पर चारों तरफ जल भराव हो गया। प्रशासन को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई वाहन पानी में फंस गये। रास्ते पर वाहनों की लंबी लाइन देखने को मिली। गत दिन कवांट, छोटाउदेपुर में दो इंच से ज्यादा बारिश हुई जबकि दाहोद में भी दो इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि, भारी बारिश गुजरात के अलावा अन्य हिस्सों में भी हो सकती है। पूर्वीय राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सोमवार को हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में भी भारी बारिश की चेतावनी होने से प्रशासन द्वारा सावधानी के सभी कदम उठाये गये है। दक्षिण पश्चिम मध्यप्रदेश पर डिप्रेशन की स्थिति पैदा हुई है जिसकी वजह से बारिश का माहौल हुआ है।

गणपति बापा लौकरिया

गणेश विसर्जन को लेकर भक्तों में रविवार को भारी उत्साह देखने को मिला। विशाल गणेश भगवान की मूर्तियों के लिए क्रेन का उपयोग भी किया गया।

१८ वर्ष पूरे नहीं तभी मतदाता सूची में नाम रजिस्ट्रेशन होंगा

बडौदा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर १५ अक्टूबर तक चलनेवाले मतदाता सूची संशोधन कार्यक्रम में आगामी १ जनवरी २०१९ तक में जो युवाओं की उम्र १८ वर्ष पूरा होता हो ऐसे युवाओं के नाम तीन महीने पहले ही मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। चुनाव आयोग द्वारा अनूठी पहल किया जाएगा। पहलीबार युवाओं पर चुनाव आयोग ने ध्यान दिया है। चुनाव आयोग और प्रशासनिक प्रशासन के यह निर्णय की वजह से राज्य के युवा वर्ग में भारी उत्साह और खुशी की भावना देखने को मिल रही है। उप जिला चुनाव अधिकारी अशोक चौधरी ने बताया है कि, १ सितम्बर से फोटोवाली मतदाता सूची संक्षिप्त संशोधन अभियान शुरू किया गया है। १५ अक्टूबर तक यह काम चलेगा। यह समय के दौरान मतदाता सूची में नाम का रजिस्ट्रेशन, नाम और एड्रेस में परिवर्तन, फोटो में परिवर्तन या सुधार, नाम छोटा कराने के लिए आदि की कामकाज शुरू किया जाएगा। ३० सितम्बर और १४ अक्टूबर को मतदान केन्द्रों पर सुबह के १० से शाम के ५ बजे तक बीएसओ-मतदाताओं की सभी अर्जी स्थल पर स्वीकार करेंगे। १ जनवरी २०१९ तक में जो भी युवाओं के १८ वर्ष पूरा होता हो यह सभी के नाम मतदाता सूची में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में यह युवा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। युवा मतदाताओं के नाम रजिस्ट्रेशन के लिए कैम्पस में भी अभियान चलाया जा रहा है और ज्यादा प्रमाण में युवा मतदाता नाम रजिस्ट्रेशन कराये ऐसे प्रयास करके मतदाता सूची में नाम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं इसकी जांच करने के लिए वेबसाइट WWW.Ceo.Gujarat.gov.in पर से मालूम किया जा सकेगा।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाईन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत।

राज्यभर में हर्षोल्लास और भक्तिभाव के बीच विसर्जन

सूरत। दस दिन के गणेश महोत्सव बाद रविवार को अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में गणेश भगवान के भक्तों द्वारा हर्षोल्लास और भक्तिभाव के बीच गणेश विसर्जन किया गया। दस दिन तक अपने-अपने क्षेत्र में विशाल पंडाल-मंडपों में पूजा विधि, आरती और भक्ति-वंदना करने के बाद रविवार को लाखों श्रद्धालुओं ने भारी उत्साह के साथ गणेश भगवान की मूर्ति को विदाई देकर इसका विसर्जन किया गया तब ''गणपति बाप्पा मौरया, पुढच्या वरसी लौकरिया'' के नारे से गूंज उठे। अहमदाबाद, बडौदा, सूरत सहित के शहरों में गणेश विसजन को लेकर प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। गणेश भगवान के विसर्जन में महिलाओं, बच्चे सहित लाखों गणेशभक्तों ने हिस्सा लिया। गणपति बाप्पा के विसर्जन रैली-जुलूस को लेकर शहर के विभिन्न मार्गो पर रविवार को ट्राफिकजाम के दृश्य देखने को मिले। एएमसी प्रशासन द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ३४ से ज्यादा कुंड बनाये गये होने से अब गणेशभक्तों द्वारा मूर्ति विसजन इसमें ही किया गया। हालांकि, प्रशासन का इनकार होने के बावजूद भी कई मामले में मूर्तियों का विसर्जन साबरमती नदी में किया गया। दस-दस दिन तक अपने घर हर गली, मोहल्ले और मंडप, पंडाल में सेवा -पूजा और आरती करने के बाद रविवार को उनको विसर्जित करने के लिए कई गणेशभक्तों की आंखें गीली हो गई। भक्तिभाव और हर्षोल्लास के बीच भगवान का विसर्जन संपन्न हुआ। रविवार को शहर सहित राज्यभर में मार्गो पर जगह-जगह गणेशभक्तों ने छोटी-बड़ी ट्रकों के साथ, टाटा-४०७, जीप-कार, रिक्शा सहित के वाहनों में डीजे, म्युजिक के ताल के साथ रैली -जुलूस विसजन यात्रा निकाली गई और बाद में भारी भक्तिभाव के साथ अगले वर्ष जल्दी आने की प्रार्थना करके मूर्तियों को विसर्जित किया गया। गणेश महोत्सव के दौरान गणेशभक्तों ने अपनी-अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुसार भगवान की पूजा की और एक, दो, पांच, नौ और दस दिन गणेश भगवान की सेवा -पूजा की गई। रविवार को गणेश महोत्सव का अंतिम दिन होने से अहमदाबाद शहर सहित राज्यभर में उत्साह के साथ गणेश भगवान की मूर्तियों का विसर्जन किया गया।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com